



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 247]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 19, 2001/भाद्र 28, 1923

No. 247]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 19, 2001/BHADRA 28, 1923

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 2001

सं. टीएएमपी/4/98-विधि.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार सभी महापत्तन न्यासों द्वारा सभी प्राइवेट टर्मिनलों को बिल भेजते समय अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग के प्रशुल्क को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने और अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग के कंटेनर प्रभारों के परिवर्तन की प्रक्रिया से संबंधित अपने 27 नवम्बर, 2000 के (बाद में 28 मार्च, 2001 को संशोधित) आदेश को लागू करता है।

अनुसूची

सं. टीएएमपी/4/98-विधि

आदेश

(30 अगस्त, 2001 को पारित)

प्राधिकरण ने पत्तनों द्वारा बिल बनाने के समय अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के प्रशुल्कों को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के बारे में सभी महापत्तन न्यासों द्वारा अपनाए जाने के लिए 27 नवंबर, 2000 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश 3 जनवरी, 2001 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

2. सभी महापत्तन न्यासों की टिप्पणियों और अन्य संगत तथ्यों पर विचार करने के बाद, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया कि बिल बनाने के प्रयोजन से डॉलर मूल्यवर्ग के प्रशुल्कों का भारतीय रुपये में परिवर्तन करने के प्रयोजन से भारतीय रिज़र्व बैंक की दैनिक दर लागू करने की वर्तमान पद्धति जारी रखी जाए। प्राधिकरण ने यह भी निर्णय किया कि जलयानों के 30 दिन से अधिक पत्तन में रुकने के मामले में विनिमय दर की 30 दिन में एक बार नियमित समीक्षा की जाए।

3. तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) ने सूचित किया कि तूतीकोरिन में जमा राशि की समय पर वसूली और बिलों के रामायोजन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की दैनिक दर प्राप्त करना संभव नहीं है। टीपीटी ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक की बाज़ार खरीद विनिमय दर स्थानीय स्टेट बैंकों से आसानी से प्राप्त हो जाती है।

4.1 टीपीटी द्वारा उल्लिखित कठिनाइयों को ध्यान में रखकर मामले पर पुनर्विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि 27 नवंबर, 2000 के आदेश के पैरा सं. 7 (i) में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :-

“पत्तनों के सुझावों को ध्यान में रखकर, दरों के मान में यथाविनिर्दिष्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसकी सहायक बैंकों या सार्वजनिक क्षेत्र की किसी अन्य बैंक द्वारा अधिसूचित बाज़ार खरीद दर लागू करने की वर्तमान पद्धति बिल बनाते समय डॉलर मूल्यवर्ग के प्रशुल्कों को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के प्रयोजन से जारी रहेगी।”

4.2 28 मार्च, 2001 का उपर्युक्त आदेश 11 अप्रैल, 2001 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था।

5. यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण के उक्त आदेश सभी महापत्तन न्यासों पर लागू किए गए हैं, प्राइवेट टर्मिनलों पर नहीं। प्राइवेट टर्मिनल दरों के मान को अनुमोदित करते समय प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशानुसार बिल बनाने के प्रयोजन से ‘सीमा शुल्क दर’ का अनुकरण जारी रखेंगे। महापत्तन न्यासों के लिए किए गए निर्णय के आलोक में दो प्रचालक प्राइवेट टर्मिनलों - पीएसए एसआईसीएल तथा एनएसआईसीटी से अनुरोध किया गया है कि उसे अपनाने के संबंध में यदि उनकी कोई टिप्पणियाँ हों तो वे उन्हें प्रस्तुत करें। उनसे प्राप्त टिप्पणियों का सार इस प्रकार है :-

पीएसए एसआईसीएल टर्मिनल लिमिटेड

- (i) मासिक सीमा शुल्क विनिमय दरों को प्रयोग में लाने की वर्तमान व्यवस्था हमारे ग्राहकों को पूरी तरह स्वीकार है क्योंकि इससे उन्हें अपनी लागत (अर्थात् लागत बचत) का बेहतर प्रबंध करने और विनिमय दरों में दैनिक परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए भारी संसाधनों का आबंटन करने (अर्थात् अतिरिक्त प्रशासनिक भार) से बचने में सुविधा होती है।
- (ii) दैनिक दर में परिवर्तन करने के लिए आज तक (प्रयोक्ताओं से) कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।
- (iii) हमारे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू ग्राहकों से प्राप्त फीडबैक से पता चलता है कि वे मासिक सीमा शुल्क विनिमय दरों को वरीयता देते हैं, यह टीपीटी की स्थिति के अनुरूप है।
- (iv) दैनिक विनिमय दर अपनाने से पीएसए एसआईसीएल को अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपये का मूल्यहास होने के कारण राजस्व में प्रतिवर्ष लगभग 0.5 मिलियन रुपये का अमिलास प्राप्त होगा।
- (v) ग्राहक सेवा और संतुष्टि दीर्घकालिक साझीदारी मूल्य के ग्राहक बनाने की सफलता का आधार है। अतः हम शक्ति की और वित्तीय हानि होने के बावजूद अपने ग्राहकों के लाभ के लिए मासिक सीमा शुल्क विनिमय दरों का प्रयोग करने की वर्तमान व्यवस्था को जारी रखना चाहेंगे।

न्हावा-शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी)

- (i) टर्मिनल प्रचालक को विदेशी मुद्रा में निधि के बाहर प्रेषण की सुविधा के लिए डॉलर मूल्यवर्ग का प्रशुल्क दिया जाता है। ग्राहकों द्वारा विनिर्दिष्ट आयात दर बाहरी भुगतानों के लिए प्राधिकृत डीलरों द्वारा विनिर्दिष्ट दरों के सबसे निकट है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) दर के बजाय सीमा शुल्क दर का प्रयोग करने की अनुमति देना अधिक तर्कसंगत होगा। आरबीआई दर वह दर है जिस पर बैंक अपने बीच लेन-देन करते हैं। महापत्तनों के विपरीत प्राइवेट प्रचालक विदेशी मुद्रा के बाहर निर्गमों का प्रबंध करने के लिए सीमा शुल्क दर को अधिक उपयुक्त विकल्प मानेंगे।
- (ii) सीमा शुल्क दर माह में एक बार घोषित की जाती है। इससे बिल बनाने की प्रक्रिया में स्थिरता आती है और दैनिक उतार-चढ़ाव नहीं रहता।
- (iii) कुछ अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के प्रशुल्क लागत प्रशुल्क (मानीटरन एवं मंडारण) हैं जिनमें सेवा देने के समय को किसी विशेष दिन की विनिमय दर से नहीं जोड़ा जा सकता। इस मामले में आयात सीमा शुल्क दर पूरे माह स्थिर रहने से अधिक उपयुक्त और तर्कसंगत होगी क्योंकि उसके अंतर्गत वह पूरी अवधि आ जाती है जिसमें सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- (iv) बीजक बनाने की तारीख को सीमा शुल्क दर पर बीजक बनाने की व्यवस्था बिना किसी समस्या के अद्यतन काम करती है और हमारी राय में केवल एकरूपता की खातिर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

6. इस मामले में 17 जुलाई, 2001 को सीएचपीटी परिसर में संयुक्त सुनवाई की गई। संयुक्त सुनवाई में निम्नलिखित निवेदन किए गए :-

पीएसए एसआईसीएल टर्मिनल लिमिटेड

- (i) हमें यदि दैनिक दर अपनाई जाए तो ट्रेकिंग की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमें प्रतिदिन जाँच रखनी होगी।
- (ii) सीमा शुल्क दर पूरे माह के लिए एक होने से स्थिरता बनी रहती है जिससे बिल बनाने में सुविधा होती है।
- (iii) सीमा शुल्क दर में कोई अस्पष्टता नहीं होगी।
- (iv) यदि हम सीमा शुल्क दर अपनाते हैं तो हमें दर को एसबीआई दर आदि में अंतरित करने में कोई समस्या नहीं होगी।

न्हावा-शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (एनएसआईसीटी)

- (i) हम पीएसए एसआईसीएल के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।
- (ii) सीमा शुल्क दर सभी के लिए आसानी से उपलब्ध है।
- (iii) सीमा शुल्क दर प्रत्येक के लिए अधिक सुविधाजनक है और विशेष रूप से स्वतः बिल बनाने के लिए उपयुक्त है।
- (iv) आरबीआई दर दोपहर 12 बजे के बाद आती है। उससे पहले बनाए जाने वाले बिलों पर किस दर का प्रयोग किया जाए ?
- (v) यदि अंतर नाममात्र का है तो 'प्रचालन की सुविधा' को क्यों न ध्यान में रखा जाए ? हमारे लिए 'सीमा शुल्क दर' लागू करना सुविधाजनक है। हमारे ग्राहक भी इसे सुविधाजनक मानते हैं।
- (vi) यदि फ्रैटन न्यासों के लिए बैंक का चयन करने का विकल्प है तो सीमा शुल्क दर का भी विकल्प क्यों नहीं दिया जाता?

कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन (सीएसएलए)

- (i) सीमा शुल्क दर का प्रयोग अधिक सुविधाजनक होगा।
- (ii) जब हम 10-15 जलयानों के लिए एक साथ बीजक बनाते हैं तो हमें 10-15 मित्र-मित्र बैंक दरों का हिसाब रखना पड़ता है। सीमा शुल्क दर लागू करना बहुत आसान होगा।

भारतीय राष्ट्रीय पोतस्वामी संघ (आईएनएसए)

- (i) सीएचपीटी में हम एसबीआई दर का अनुवर्तन करते हैं। उसमें कोई समस्या नहीं है।
- (ii) एकरूपता की दृष्टि से हम एसबीआई दर को वरीयता देते हैं।
- (iii) टर्मिनलों को कुछ प्रशासनिक समस्याएँ हो सकती हैं लेकिन हमें कोई समस्या नहीं है।

7. सीएसएलए और एमएएनएसए ने भी लिखित निवेदन प्रस्तुत करते हैं जिनका सार इस प्रकार है :-

कंटेनर शिपिंग लाइन्स एसोसिएशन

- (i) प्राइवेट टर्मिनलों द्वारा अपनाई जा रही सीमा शुल्क विनियम दर लागू करने की वर्तमान पद्धति उपयुक्त और व्यावहारिक है। उन्हें बिल बनाने में कोई समस्या नहीं आती।
- (ii) शिपिंग लाइनों की दृष्टि से इससे निर्बाध भुगतान करने और मालिक के खर्चों का लेखा तैयार करने में सुविधा होती है। हमने यह भी नोट किया है कि कस्टम को भी कस्टम द्वारा अधिसूचित विनियम दर के प्रचालन में कोई समस्या नहीं होती और यह कस्टम मूल्य के संबंध में हुए विश्व व्यापार संगठन क्रार के अनुरूप है और हमारे लक्ष्य ग्राहकों के लिए फायदेमंद हैं।
- (iii) प्राइवेट टर्मिनलों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति को जारी रखा जाए।

मुंबई एवं न्हावा-शेवा शिप एजेंट एसोसिएशन

- (i) विशेष स्थिति में, जैसी कि वीपीटी में घटी जिसमें एक जलयान लगभग तीन वर्ष तक ठहरा, जलयान की 'चालन तारीख' को प्रचलित विनियम दर निर्धारित करना उचित होगा।
- (ii) बर्थ किराया, पत्तन देय शुल्क, पायलट शुल्क, रस्सा लंगर शुल्क आदि के मामले में, चालन की तारीख को प्रचलित विनियम दर लागू होगी।
- (iii) कंटेनरों पर भूमि किराये/कागों पर विलंब भाड़े के मामले में कंटेनर/कागों कई माह, यहाँ तक कि कई वर्ष भी पड़े रह सकते हैं, ऐसे मामलों में भूमि किराये का बिल प्रति माह उस 'माह के अंत' की विनियम दर को लागू करके बनाया जा सकता है।
- (iv) दैनिक लेन-देन जैसे मजदूरों की सप्लाई के मामले में कार्य की तारीख को प्रचलित दर लागू की जा सकती है।
- (v) सामान्यतया जब रुपया-डॉलर विनियम दर में एक ही दिशा में उतार-चढ़ाव होता हो ऐसे में पूरे माह के लिए स्थिर दर रखना तर्कसंगत नहीं लगता।

8. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्रित समग्र सूचना के संदर्भ में और संयुक्त सुनवाई में दिए गए तर्कों की दृष्टि से निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :-

- (i) इस मामले में किए गए प्रयास का सार पत्तन न्यासों और प्राइवेट टर्मिनल प्रचालकों द्वारा बिल बनाते समय डॉलर मूल्यवर्ग के प्रशुल्कों के भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के मामले में एकरूपता लाना है।
- (ii) हालाँकि शुरु में यह प्राधिकरण इस प्रयोजन से 'सीमा शुल्क दर' अपनाने के पक्ष में था परंतु पत्तन न्यासों के भत्तों पर विचार करने के बाद दरों के मान में यथा विनिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंकों या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य द्वारा अधिसूचित बाज़ार खरीद दरों को अपनाने का निर्णय किया गया।
- (iii) प्राधिकरण के उक्त आदेश को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया और सभी पत्तन न्यासों के लिए लागू किया गया। दुर्भाग्य से प्राइवेट टर्मिनल प्रचालकों पर इसे लागू करना नज़र अंदाज़ कर दिया गया। अतः इस मामले पर प्राइवेट टर्मिनल प्रचालकों के साथ चर्चा करने और इस अंतर को दूर करने का प्रयास किया गया।
- (iv) इस संबंध में पद्धति की एकरूपता की वकालत करने के बाद इस प्राधिकरण के लिए दो प्रकार की पद्धतियों को प्रचलित करना व्यर्थ होगा। अतः ऐसी परिस्थिति में प्राइवेट टर्मिनलों से महापत्तन न्यासों के लिए निर्धारित पद्धति को अपनाने की अपेक्षा की गई है।
- (v) वर्तमान में प्रचालन करने वाले दो प्राइवेट टर्मिनलों - एनएसआईसीटी और पीएसए एसआईसीएल ने 'सीमा शुल्क दर' को जारी करने की अपनी वरीयता को दोहराया है। उनके अनुसार इससे सेवाओं की लागत में स्थिरता, बिल बनाने में सरलता, ग्राहकों की वरीयता की स्वीकृति, 'दर' की आसानी से उपलब्धता और किसी भी प्रकार की संदग्धता में कमी आती है।
- (vi) सीएसएलए ने भी 'सीमा शुल्क दर' की वरीयता का समर्थन यह कहकर किया है कि मिश्र-मिश्र बैंकों की मिश्र-मिश्र दरें निर्धारित करने की बोझिल प्रक्रिया की तुलना में इसे अपनाना अधिक सुविधाजनक है।
- (vii) रोचक बात यह है कि एमएएनएसए और आईएनएसए दोनों ने पत्तन न्यासों द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति को अपनाने का विकल्प दिया है। एमएएनएसए ने जोर देकर कहा है कि ऐसी स्थिति में जब रुपया-डॉलर विनियम दर सामान्यतया एक ही दिशा में घटती-बढ़ती है, पूरे माह के लिए नियत दर लागू करना उन्हें तर्कसंगत नहीं लगता।
- (viii) स्पष्ट है कि उपलब्ध दोनों विकल्पों के बारे में मत बराबर-बराबर विभाजित हैं। प्राइवेट टर्मिनल ऑपरेटरों ने कहा है कि वे सुलभता और स्थिरता के कारणों से 'सीमा शुल्क दर' को वरीयता देते हैं हालाँकि इसे अपनाने से उन्हें राजस्व की

हानि होगी। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना होगा कि आज के कंप्यूटर युग में 'सीमा शुल्क दर' या 'बैंक दर' की उपलब्धता को किसी पत्तन न्यास या प्राइवेट टर्मिनल के लिए समस्या नहीं माना जा सकता। और एमएएनएसए के इस पुरजोर तर्क को ध्यान में रखकर कि जब रुपया-डॉलर विनिमय दर सामान्यतया एक ही दिशा में घटती-बढ़ती है, पूरे माह के लिए नियत दर लागू करना उन्हें तर्कसंगत नहीं लगता, स्थिरता कारक को भी किसी विशेष लाभ का नहीं माना जा सकता।

- (ix) दोनों प्राइवेट टर्मिनल प्रचालकों ने अपने प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में चाहे जो भी वकालत की हो परंतु उन्होंने यह भी कहा है कि हालाँकि वे 'सीमा शुल्क दर' को अपनाने को वरीयता देते हैं तथापि उन्हें आरबीआई आदि दर को अपनाने में भी कोई समस्या नहीं होगी। प्राइवेट टर्मिनल प्रचालकों की एक ही लाइन में चलाने की इच्छा से इस प्राधिकरण के लिए इस निर्णय को लागू करना और भी आसान हो जाता है कि वह प्राइवेट टर्मिनल प्रचालकों से महापत्तन न्यासों के लिए अनुमोदित पद्धति को अपनाने के लिए कहे।
- (x) महापत्तन न्यासों के मामलों में इस प्राधिकरण द्वारा लिया गया पूर्व निर्णय अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग में जलयान संबंधी प्रमारों और कंटेनर संबंधी प्रमारों के बिल बनाने के लिए लागू है। एनएसआईसीटी और पीएसए एसआईसीएल दोनों ही कोई भी समुद्री सेवाएँ प्रदान नहीं करते। ये सेवाएँ संबंधित भूस्वामी पत्तन न्यासों द्वारा प्रदान की जाती हैं। अतः ऐसी स्थिति में केवल कंटेनर संबंधी प्रमारों के पुनः परिवर्तन के मामले में पहले से निर्धारित प्रक्रिया ही इन दो प्राइवेट टर्मिनलों के संबंध में प्रासंगिक होगी।
- (xi) महापत्तन न्यासों के मामले में पत्तन सीमा में जलयानों के प्रवेश की तारीख और पत्तन परिसरों में कंटेनरों के आने की तारीख को क्रमशः आयात एवं निर्यात कंटेनरों के बिल बनाते समय पुनः परिवर्तन की अंतिम तारीख (कर ऑफ प्याइंट) है। महापत्तन न्यासों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप (आयात कंटेनरों के मामले में) टर्मिनल में जलयान के प्रवेश की तारीख और (निर्यात कंटेनरों के मामले में) टर्मिनल परिसरों में कंटेनरों के आने की तारीख को प्राइवेट टर्मिनलों द्वारा बिल बनाते समय पुनः परिवर्तन की अंतिम तारीख (कट ऑफ प्याइंट) माना जाएगा।

9.1 परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से तथा समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण अपने 27 नवंबर, 2000 के (28 मार्च, 2001 को यथा संशोधित) आदेश में शामिल निम्नलिखित प्रावधानों को महापत्तन न्यासों के भीतर प्रचालन करने वाले प्राइवेट टर्मिनलों पर लागू करने का निर्णय करता है :-

- (i) दरों के मान में यथा विनिर्दिष्ट भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसकी सहायक बैंकों या सार्वजनिक क्षेत्र की किन्हीं अन्य बैंकों द्वारा अधिसूचित बाज़ार खरीद विनिमय दरें बिल बनाते समय डॉलर मूल्यवर्ग के प्रशुल्कों को भारतीय रुपयों में परिवर्तित करने के प्रयोजन से लागू होंगी।
- (ii) पत्तन में तीस दिन से अधिक ठहरने वाले जलयानों के मामलों में जलयान के आगमन की तारीख से तीस दिन में एक बार विनिमय दर की नियमित समीक्षा की जाएगी। ऐसे मामलों में बिल बनाने का आधार समीक्षा की तारीख को प्रचलित उपयुक्त विनिमय दर के संदर्भ में तदनुसार बदल जाएगा।
- (iii) अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के कंटेनर संबंधी प्रमारों की वसूली समतुल्य भारतीय रुपयों में की जाएगी। इस प्रयोजन से, (आयात कंटेनरों के मामले में) टर्मिनल में जलयान के प्रवेश की तारीख को और (निर्यात कंटेनरों के मामलों में) टर्मिनल परिसरों में कंटेनरों के आने की तारीख को प्रचलित बाज़ार खरीद दर डॉलर मूल्यवर्ग के प्रमारों को भारतीय रुपयों में पुनः परिवर्तित करने के लिए लागू होगी।

9.2 एनएसआईसीटी और पीएसए एसआईसीएल को निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त पैराग्राफ 9.1 में दिए गए प्रावधानों को शामिल करने के लिए दरों के मान में तदनुसार संशोधन करें।

10. यह आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने की तारीख से 30 दिन बाद प्रभावी होगा।

एस. सत्यम, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2001/असा.]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2001

No. TAMP/4/98-Misc.—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends its Order dated 27 November, 2000, (subsequently amended on 28 March, 2001) relating to re-conversion of US dollar denominated tariffs into Indian rupees and the procedure for re-conversion of container charges denominated in US dollar terms at the time of billing by the Major Port Trusts to all the Private Terminals therein also as in the Order appended hereto.

SCHEDULE
No. TAMP/4/98-Misc.

ORDER

(Passed on this 30th day of August 2001)

This Authority had passed an Order on 27 November 2000 about re-conversion of US dollar denominated tariffs in to Indian Rupees at the time of billing by the Ports for common adoption by all the Major Port Trusts. The Order was notified in the Gazette of India on 3 January 2001.

2. After considering the comments of all the Major Ports and other relevant factors, it was *inter alia* decided that the existing practice of applying the RBI daily rate should continue for the purpose of conversion into Indian rupees of the dollar denominated tariffs for the purpose of billing. The Authority also prescribed a regular review of the exchange rate once in 30 days in case of vessels staying in ports for more than 30 days.

3. The Tuticorin Port Trust (TPT) informed that it was not possible to obtain the daily rate of RBI at Tuticorin for timely collection of deposits and settlement of bills. The TPT indicated that the market buying exchange rate of the State Bank of India was easily obtainable from the local SBI.

4.1. In view of the difficulties explained by the TPT, the matter was again considered and it was decided to amend paragraph No. 7 (i) of the Order dated 27 November 2000 as follows:

"Bearing in mind the suggestions of the Ports, the existing practice of applying the market buying rates notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its subsidiaries or any other public sector banks, as specified in the Scale of Rates, shall continue for the purpose of conversion to Indian Rupee of dollar denominated tariffs at the time of billing".

4.2. The above Order dated 28 March 2001 was notified in the Gazette of India on 11 April 2001.

5. It is noteworthy that this Authority's Orders in reference have been made applicable to all the Major Port Trusts and not to Private Terminals. The Private Terminals continue to follow the 'Customs Rate' for the purpose of billing, as ordered by the Authority while approving their Scales of Rates. In the light of the prescription made for the Major Port Trusts, the two operating Private Terminals – the PSA SICAL and the NSICT – have been requested to furnish their comments, if any, in connection with adoption of the same. The comments received from them are summarised below:

The PSA SICAL Terminals Limited

- (i). The existing arrangement of using Monthly Customs Exchange Rates is well received by our customers because it allows them to better manage their cost (i.e., cost savings), and avoid allocating huge resources to track and implement the daily changes in exchange rates (i.e., additional administrative burden).
- (ii). To-date, there is no request (from the users) to change this to a daily rate.
- (iii). Feedback gathered from both our international and domestic customers indicates that they prefer the Monthly Customs Exchange Rates it is in line with TPT's position.

- (iv). By adopting a daily exchange rate, the PSA SICAL would gain an estimated Rs.0.5 million per year in revenue because of the depreciating Rupees against the US dollars.
- (v). Customer service and satisfaction are fundamental to the success of building long-term partnership valued customers. Therefore, we would like to continue with our existing arrangement to use Monthly Customs Exchange Rates despite the potential and financial loss, for the benefits of our customers.

The Nhava Sheva International Container Terminal Limited (NSICT)

- (i). The dollar denominated tariff is granted to the terminal operator to facilitate outward remittance of funds in foreign currency. The import rate specified by the Customs is the nearest to the rates specified by the authorised dealers for outward payments. Hence it is more logical to be permitted the use of customs rate rather than the RBI reference rate. RBI reference rate is the rate at which the banks enter into transactions among themselves. Unlike the Major Ports, private operator will prefer to have the Customs reference rate as more suitable option for managing the outward foreign currency flows.
- (ii). The Customs Rate is declared once a month. This gives more stability to the billing process and avoids the daily fluctuations.
- (iii). Few of the US dollar denominated tariffs are period costs (reefer monitoring and storage) where the time of providing the service can not be linked to a particular day's exchange rate. In this case the import Customs Rate, which is stable throughout the month is more appropriate and logical as it covers the entire period during which the services are rendered.
- (iv). The arrangement of invoicing at Customs reference rate on the date of invoicing has worked without any major problem up to date and in our opinion does not require any change just for the sake of uniformity.

6. A joint hearing in this case was held at the CHPT premises on 17 July 2001. At the joint hearing, the following submissions were made:

The PSA SICAL Terminal Limited

- (i). We may face problems of tracking, if the daily rate is adopted. Everyday we have to check.
- (ii). Customs Rate is one for a month and, therefore, there is stability which facilitates in billing also.
- (iii). There is no ambiguity in the Customs Rate.
- (iv). While we prefer the Custom Rate, we have no problem in shifting to the SBI, etc., rate.

The Nhava Sheva International Container Terminal Limited (NSICT)

- (i). We endorse the PSA SICAL view point.
- (ii). Customs Rate is easily available to all.
- (iii). Customs Rate is much more convenient to every body specially suited to automated billing.
- (iv). RBI rate comes after 12 noon. For bills made before that time, which rate must be used?

- (v). If the difference is nominal, why not consider 'convenience of operation'? We find it convenient to apply the 'Customs Rate'. Our customers also find it convenient.
- (vi). If Port Trusts have option to choose between banks, why not give Customs Rate also as an option?

Container Shipping Lines Association (CSLA)

- (i). Usage of Customs Rate will be more convenient.
- (ii). When we get invoices for 10-15 vessels at a time we have to reckon with 10-15 different bank rates. It will be far simpler with Custom Rate.

Indian National Shipowners Association (INSA)

- (i). At the CHPT, we follow SBI rate. There has been no problem.
- (ii). We prefer the SBI rate from a uniformity point of view.
- (iii). Terminals may have some administrative problems. But, we have no difficulty.

7. The CSLA and the MANSA have also submitted written submissions which are summarised below:

Container Shipping Lines Association

- (i). The present practice followed by the Private Terminals of applying the Customs exchange rate is suitable and practical. They have not faced any difficulties in billing.
- (ii). From the Lines' point of view, this facilitates smooth payments and accounting of the Principal's expenses. We have also noted that even Customs has not faced any difficulty in the operation of Customs notified exchange rate and it is consistent with the World Trade Organisation Agreement on Customs value and this is beneficial to the ultimate customer.
- (iii). The practice followed by the Private Terminals be allowed to continue.

Mumbai and Nhava Sheva Ship - Agents' Association

- (i). In a peculiar situation like the one happened at the VPT, where a vessel stayed for almost three years, it is advisable to fix exchange rate on the vessel's "sailing date".
- (ii). In case of berth hire, port dues, pilotage, tugs' anchorage fees, etc., the exchange rate prevailing at the date of sailing shall apply.
- (iii). In case of ground rent on containers / demurrage on cargo, where they may be lying for months together, even years, in such cases, the ground rent may be billed every month applying 'month end' exchange rate.
- (iv). In case of daily transactions such as labour supply, rate on the date of activity can be applied.
- (v). We see no logic in having constant rate for a full month, when rupee-dollar exchange rate fluctuates generally in one direction.

8. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, and taking into account the arguments advanced at the joint hearing the following position emerges:

- (i). The substance of the effort in this case is to bring about uniformity in the matter of re-conversion of dollar-denominated tariffs to Indian rupees at the time of billing by the Port Trusts and Private Terminal Operators.
- (ii). Although this Authority was originally in favour of adopting the 'Customs Rate' for the purpose, after reckoning with the views of the Port Trusts, it was decided to adopt 'the market buying rates notified by the Reserve Bank of India, the State Bank of India or its Subsidiaries, or any other Public Sector Banks as specified in the Scale of Rates'.
- (iii). The said Order of this Authority was notified in the Gazette of India and made applicable to all the Port Trusts. Unfortunately, its application to Private Terminal Operators was lost sight of. The effort was, therefore, pursued to take up this issue with the Private Terminal Operators and cover this gap.
- (iv). Having advocated uniformity of practice in this regard, it will be incongruous for this Authority to allow two sets of practice to prevail. That being so, in the given circumstance, the Private Terminals have been required to switch over to the system prescribed for the Major Port Trusts.
- (v). The two Private Terminals operating at present – the NSICT and the PSA SICAL – have reiterated their preference for continuing with the adoption of the 'Customs Rate'. According to them, this makes for stability in costing of services, simplicity in billing, acceptance of customer preference, easy availability of the 'rate', and lack of any ambiguity.
- (vi). The CSLA has also endorsed the preference for the 'Customs Rate' by saying that its adoption will be more convenient as against the cumbersome tracking required to ascertain 'bank rates' from different banks.
- (vii). Interestingly, the MANSA and the INSA have both opted for the system preferred by the Port Trusts. The MANSA has emphatically stated that they see no logic in having a constant rate for a full month when the rupee-dollar exchange rate fluctuates generally in one direction.
- (viii). As can be seen, the opinions about the two options available are evenly divided. Incredibly, the Private Terminal Operators have stated they prefer the 'Customs Rate' for reasons of easy availability and stability even though its adoption results in loss of revenue to them! It has to be recognised in this context that, in today's computer-age, availability of the 'customs rate' or the 'bank rate' cannot be said to be a problem for any Port Trust or Private Terminal. And, bearing in mind the emphatic averment of the MANSA about there being no logic in having a constant rate for a full month when the rupee-dollar exchange rate fluctuates generally in one direction, the stability factor cannot also be seen to have any particular advantage.
- (ix). Irrespective of the *pros* and *cons* of the proposition advocated by them, both the Private Terminal Operators have nevertheless stated that, whereas their preference will be for adoption of the 'Customs Rate', they will have no problem in shifting to the 'RBI etc., 'Rate'. This willingness of the Private Terminal Operators to fall in line makes it easier for enforcement of this Authority's (earlier) decision about requiring the Private Terminal Operators to switch over to the system approved for the major Port Trusts.
- (x). The prescription earlier made by this Authority in the cases of Major Port Trusts is applicable for billing of vessel-related charges and container related

charges which are denominated in US \$ terms. Both the NSICT and the PSA SICAL do not provide any marine related services. These are provided by the respective land lord port trusts. That being so, the procedure already prescribed in respect of reconversion of container related charges only will be relevant in respect of these two Private Terminals.

- (xi). In the case of major port trusts, the date of entry of vessel into the port limit and date of arrival of the containers in the Port premises have been prescribed as the cut-off points for reconversion at the time of billing of import and export containers respectively. In conformity with the procedure prescribed for the major ports, the date of entry of the vessel into the Terminal (in case of import containers) and the date of arrival of containers in the Terminal premises (in case of export containers) can be taken as the cut-off points for reconversion at the time of billing by Private Terminals.

9.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority decides to extend the following provisions contained in its Order dated 27 November 2000, (as amended on 28 March 2001) to Private Terminals operating within the Major Port Trusts:

- (i). The market buying exchange rates notified by the Reserve Bank of India, State Bank of India or its subsidiaries or any other public sector banks, as specified in the Scale of Rates, shall be applied for the purpose of conversion to Indian rupees of dollar denominated tariffs at the time of billing.
- (ii). A regular review of the exchange rate shall be made once in thirty days from the date of arrival of the vessel in cases of vessels staying in the port for more than thirty days. In such cases, the basis of billing shall change prospectively with reference to the appropriate exchange rate prevailing at the time of the review.
- (iii). Container related charges denominated in US dollar terms shall be collected in equivalent Indian rupees. For this purpose, the market buying rate prevalent on the date of entry of the vessel into the Terminal (in case of import containers) and on the date of arrival of containers in the Terminal premises (in cases of export containers) shall be applied for re-conversion of the dollar denominated charges into Indian rupees.

9.2. The NSICT and the PSA SICAL are directed to amend their Scales of Rates accordingly to incorporate the provisions given in paragraph 9.1 above.

10. This Order will come into effect thirty days after its notification in the Gazette of India.

S. SATHYAM, Chairman

[ADVT. III/IV/143/2001/Exty.]